भारत-अमेरिका संबंधों को नई रफ्तार

एआई और रक्षा सहयोग पर बढ़ा जोर

वाशिंगटन, 30 जून. भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है. दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि रणनीतिक साझेदारी अब पारंपरिक कूटनीति और रक्षा सहयोग से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, सप्लाई चेन, निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए आयाम हासिल कर रही है.

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम (यूएसआईएसपीएफ) लीडरशिप समिट में दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत-अमेरिका संबंध साझा रणनीतिक हितों, तकनीकी सहयोग और निवेश के कारण एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं.

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता अपने अंतिम चरण में है. वहीं, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत के आर्थिक सुधार, विनिर्माण क्षमता और उच्च तकनीक में निवेश ने उसे वैश्विक विकास और भरोसेमंद साझेदारी का प्रमुख केंद्र बना दिया है. उनके अनुसार, भारत इस दशक के अंत तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

> पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लोगों के बीच मजबूत संबंध दोनों देशों की साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने यूएसआईएसपीएफ की कॉफी टेबल बुक 'वी द पीपल: 250 वॉयसेज दैट हैव शेप्ड द यूएस-इंडिया रिलेशनशिप का भी विमोचन किया. समिट के दौरान यह स्पष्ट संदेश सामने आया कि भारत-अमेरिका संबंध अब केवल कूटनीति और रक्षा तक सीमित नहीं हैं. भविष्य में तकनीक, मजबूत सप्लाई चेन, विनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आधार बनेंगे.

राजीव कुमार बने एचडीएफसी के चेयरमैन

नई दिल्ली, 30 जून. देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया पार्ट-टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है. बैंक के बोर्ड ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, हालांकि यह नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी. उन्हें तीन साल की अवधि के लिए यह जिम्मेदारी दी गई है.

राजीव कुमार बैंक के मौजूदा चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती की जगह लेंगे, जिन्होंने इसी साल मार्च में नैतिक चिंताओं का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था.

कैबिनेट ने एनआईआईएफ में किया निवेश

सरकार की कुल निवेश प्रतिबद्धता बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये हुई

बुनियादी ढांचा और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को मिलेगा नया बल

नई दिल्ली, 30 जून केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में निवेश को गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के नए और आगामी फंडों के लिए 30,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर इस फैसले के बाद एनआईआईएफ में केंद्र सरकार की कुल निवेश प्रतिबद्धता बढ़कर 60,000 करोड़ रुपये हो गई है. सरकार का मानना है कि इस कदम से दीर्घकालिक पूंजी जुटाने, निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा देश में आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को नई गति मिलेगी.

सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह एनआईआईएफ के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी. यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब भारत तेज आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश पर जोर दे रहा है.

एनआईआईएफ भारत सरकार समर्थित एक निवेश मंच है, जिसका संचालन और प्रबंधन पेशेवर तरीके से नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड द्वारा किया जाता है.

> सरकार का कहना है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा, आधुनिक ऊर्जा नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और बेहतर लॉजिस्टिक्स बेहद आवश्यक हैं. एनआईआईएफ में अतिरिक्त निवेश का यह निर्णय इन्हीं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इससे आने वाले वर्षों में बड़े अवसंरचना निवेश, आर्थिक विकास और वैश्विक पूंजी आकर्षित करने की भारत की क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

इनेरा-क्रॉपनेक्स्ट समझौता, जैविक खेती को बढ़ावा

नयी दिल्ली, 30 जून इनेरा क्रॉप साइंस और क्रॉपनेक्स्ट सॉल्यूशंस ने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के किसानों तक विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान पहुंचाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है.

सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस साझेदारी का लक्ष्य 5,000 से ज्यादा चैनल भागीदारों और खुदरा विक्रेताओं के नेटवर्क के जरिए 65 लाख से अधिक किसानों तक पहुंच बनाना है. साथ ही, करीब 20 लाख एकड़ खेती वाले क्षेत्र में जैविक कृषि उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है. दोनों कंपनियों का कहना है कि विज्ञान आधारित जैविक कृषि समाधान इन चुनौतियों से निपटने में अहम् भूमिका निभा सकते हैं. ये खेती में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, फसल की पैदावार सुधारने, मिट्टी की सेहत मजबूत करने और किसानों को ज्यादा स्थायी खेती अपनाने में मदद करते हैं.

इनेरा ने विज्ञान आधारित अनेक जैविक कृषि समाधान प्रस्तुत किये हैं जो मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने और फसलों को मजबूत करने में मदद करती है, वहीं क्रॉपनेक्स्ट पूर्वी भारत में अपने मजबूत वितरण नेटवर्क, रिटेलर कनेक्ट और किसानों तक सीधी पहुंच के जरिए इस साझेदारी को मजबूती देगा. दोनों कंपनियां मिलकर खेती से जुड़ी नयी तकनीकों को किसानों के करीब लाने का काम करेंगी.

5जी फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेगमेंट में मजबूत पकड़

मई में करीब 4 लाख नए ग्राहक जुड़े; ट्राई रिपोर्ट में जियो अग्रणी

नई दिल्ली, 30 जून 2026. रिलायंस जियो को ब्रॉडबैंड बाजार में अपनी सेवाओं जियोफाइबर और जियोएयरफाइबर के जरिए लगातार मजबूत बढ़त मिल रही है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, फिक्स्ड वायर्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में जियोफाइबर के पास करीब 1.44 करोड़ ग्राहक हैं, जिससे यह इस क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है. वहीं 5त्र फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेगमेंट में भी जियोएयरफाइबर तेजी से विस्तार कर रहा है.

5जी फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है, जिन्हें बिना पारंपरिक केबलिंग के हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है. यह तकनीक घरों के साथ-साथ ऑफिस, दुकानें, स्कूल और छोटे व्यवसायों में भी तेजी से अपनाई जा रही है. मई 2026 के अंत तक जियोएयरफाइबर के ग्राहकों की संख्या लगभग

89.68 लाख तक पहुंच गई.

रिपोर्ट के अनुसार, मई महीने में जियो ने फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेगमेंट में लगभग 4 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि इसके निकटतम प्रतिस्पर्धी एयरटेल की वृद्धि लगभग 10 हजार रही. इस तरह इस सेगमेंट में जियो की हिस्सेदारी करीब 78.4 प्रतिशत हो गई है, जो उसकी मजबूत पकड़ को दर्शाती है. फिक्स्ड वायर्ड ब्रॉडबैंड में भी जियो की स्थिति मजबूत बनी हुई है. इस सेगमेंट में जियोफाइबर के 1.44 करोड़ ग्राहक हैं, जबकि एयरटेल के पास करीब 1.09 करोड़ ग्राहक दर्ज किए गए हैं. इससे स्पष्ट है कि पारंपरिक ब्रॉडबैंड बाजार में भी जियो अपनी पकड़ बनाए हुए है. देश में कुल ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़कर 108.01 करोड़ तक पहुंच गई है. कुल ग्राहकों में जियो का हिस्सा सबसे बड़ा है और कंपनी के पास लगभग 52.96 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक हैं, जिससे वह बाजार में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है.

> मोबाइल सेवाओं के क्षेत्र में भी जियो की स्थिति मजबूत है. मई 2026 में कंपनी का एक्टिव यूजर शेयर 44.2 प्रतिशत रहा, जो यह दर्शाता है कि नेटवर्क पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं के मामले में भी जियो अग्रणी है. विशेषज्ञों का मानना है कि 5जी और फिक्स्ड वायरलेस तकनीक के विस्तार से आने वाले समय में ब्रॉडबैंड बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज होगी.

भारत का विदेशी कर्ज 762.8 अरब डॉलर

मार्च 2026 तक कुल विदेशी ऋण में 26.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी

विदेशी कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात भी बढ़ा

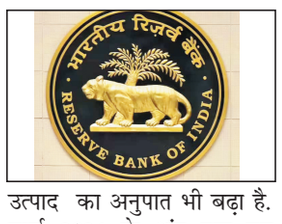

नई दिल्ली, 30 जून: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 के अंत तक भारत का कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 762.8 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 72.15 लाख करोड़ रुपये) हो गया है. यह एक वर्ष पहले की तुलना में 26.3 अरब डॉलर अधिक है.

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट 'मार्च 2026 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज' में यह जानकारी दी. आरबीआई के अनुसार, भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से विदेशी कर्ज के मूल्यांकन पर 24.6 अरब डॉलर का प्रभाव पड़ा. केंद्रीय बैंक ने कहा कि यदि इस मूल्यांकन प्रभाव को शामिल नहीं किया जाए, तो मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 तक विदेशी कर्ज में वास्तविक वृद्धि 26.3 अरब डॉलर के बजाय 51 अरब डॉलर होती.

रिपोर्ट के मुताबिक, देश का विदेशी कर्ज और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात भी बढ़ा है. मार्च 2026 के अंत तक यह अनुपात 20.8 प्रतिशत दर्ज किया गया, जबकि मार्च 2025 के अंत में यह 19.8 प्रतिशत था. आरबीआई ने बताया कि मार्च 2026 तक दीर्घकालिक विदेशी कर्ज, जिसकी मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक होती है, 613.5 अरब डॉलर रहा. यह पिछले वर्ष की तुलना में 11.6 अरब डॉलर अधिक है.

वहीं, कुल विदेशी कर्ज में अल्पकालिक कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 19.6 प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 18.3 प्रतिशत थी. विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले अल्पकालिक कर्ज का अनुपात भी बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया, जबकि मार्च 2025 के अंत में यह 20.1 प्रतिशत था. मुद्रावार हिस्सेदारी की बात करें तो मार्च 2026 के अंत में भारत के कुल विदेशी कर्ज में अमेरिकी डॉलर आधारित कर्ज की हिस्सेदारी सबसे अधिक 55.5 प्रतिशत रही.

गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी ऋण में वृद्धि दर्ज की गई

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान सामान्य सरकार का बकाया विदेशी कर्ज घटा है, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी ऋण में वृद्धि दर्ज की गई. विदेशी कर्ज के विभिन्न घटकों में ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक 34.7 प्रतिशत रही. इसके बाद मुद्रा एवं जमा 22.3 प्रतिशत, व्यापारिक ऋण और अग्रिम 19 प्रतिशत तथा ऋण प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 16.1 प्रतिशत दर्ज की गई

पश्चिम रेलवे ने स्पेशल ट्रेन फेरों को बढ़ाया

अहमदाबाद, 30 जून पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद-दरभंगा एवं गांधीधाम-भागलपुर स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तारमार्ग परिवर्तन के साथ विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा.

यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन एवं आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ती हुई यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद-दरभंगा तथा गांधीधाम-भागलपुर विशेष किराया स्पेशल ट्रेनों के फेरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है. साथ ही, उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर आरएलडीए कार्य के कारण इन ट्रेनों का संचालन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा. ट्रेन संख्या 09465/09466 अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं.

यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग वाया छायापुरी, रतलाम, उज्जैन, गुना, बिना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर होकर चलेगी.

ट्रेन संख्या 09451/09452 गांधीधाम-भागलपुर-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक शुक्रवार) के फेरे 03 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल (प्रत्येक सोमवार) के फेरे 06 जुलाई, 2026 से 03 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किए गए हैं.

पीएफसी-आरईसी विलय योजना को मंजूरी

नयी दिल्ली, 30 जून विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सरकारी उपक्रमों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडलों ने दोनों कंपनियों के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

बिजली मंत्रालय की मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार बोर्ड ने आरईसी को पीएफसी में विलीन करने की योजना को स्वीकृति दे दी है. आरईसी के पीएफसी में विलय होने से पीएफसी के कर्ज कारोबार का पोर्टफोलियो बढ़ कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा.

विलय की यह योजना सभी विनियामकी और अधिनियमित स्वीकृतियों और सहमतियों के बाद पूरी होगी. इसमें दोनों कंपनियों के संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों तथा सभी प्रासंगिक नियामक और सरकारी प्राधिकरणों से अनुमोदन शामिल हैं. विलय के बाद काम करने वाला उपक्रम भी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 'सरकारी कंपनी' बना रहेगा तथा उसमें केंद्र सरकार की बहुमत की हिस्सेदारी बनी रहेगी.

समाचार विशेष

कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर तेज

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर ही असंतोष के स्वर तेज होने लगे हैं. राज्यसभा सदस्य और बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी की चुनावी रणनीति, नेतृत्व और संगठनात्मक फैसलों पर खुलकर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने इशारों-इशारों में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की कार्यशैली पर भी निशाना साधा. दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को अखिलेश प्रसाद सिंह संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि पार्टी में अक्सर ऐसे लोगों को प्रभारी बना दिया जाता है, जिनका जमीनी राजनीति से कोई खास संबंध नहीं होता. उन्होंने कहा कि यदि उन्हें प्रदेश नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलता रहता, तो संभव है कि कांग्रेस केवल पांच-छह सीटों तक सीमित नहीं रह जाती. अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि जब वह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब संगठन में कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शाहनवाज आलम उनके कार्यकाल में एआईसीसी सचिव बने थे. लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद जो राजनीतिक परिणाम सामने आए, वह किसी से छिपे नहीं हैं.

उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को चार सीटों पर जीत दिलाने में उनकी भूमिका रही थी. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस द्वारा सामाजिक न्याय और जातीय भागीदारी के मुद्दे को प्रमुखता देने की रणनीति पर भी टिप्पणी की.

चुनावी नतीजों का दिया उदाहरण

अखिलेश सिंह ने कहा कि आबादी के अनुपात और चुनावी सफलता के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यादव समुदाय को 28 सीटें मिलीं, जबकि कई अपेक्षाकृत कम आबादी वाले वर्गों के उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंचे. उनके अनुसार, ब्राह्मण समुदाय की आबादी लगभग 3.5 प्रतिशत होने के बावजूद 17 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे. इसी तरह अन्य सवर्ण वर्गों के उम्मीदवारों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में लगभग 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अपर कास्ट वर्गों का हो गया. अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि चुनावी परिणाम आने के बाद उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी इस मुद्दे पर सवाल किया था.

यूपी बीजेपी की नई सोशल इंजीनियरिंग

क्या पंकज चौधरी की टीम पीडीए को दे पाएगी चुनौती?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरु कर दिया है. पक्ष हो या विपक्ष दोनों ने ही सियासी बयानबाजी के साथ अपनी-अपनी गोटियां सेट करने में लग गए हैं.

इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर व्यापक बदलाव करते हुए कुछ बड़े फेरबदल किया है. जिसका सीधा असर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर पड़ सकता है. बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले बड़े झटके से सीखते हुए अब नई

रणनीति पर चलने का फैसला किया है. पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के सात महीने बाद अब पार्टी ने उनकी नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है. बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के जरिए समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फॉर्मूले का मुकाबला करने की रणनीति तैयार की है.

सामाजिक संतुलन बनाने में लगी बीजेपी- उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सरकार और संगठन के बीच समाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की कमान जहां परंपरागत सवर्ण नेतृत्व के पास है, वहीं सगंठन की जिम्मेदारी ओबीसी समाज से आने वाले पंकज चौधरी के पास है और अब नई प्रदेश टीम के गठन में इसी संतुलन की झलक साफ देखने को मिलती है.

पंकज चौधरी के सामने बड़ी चुनौती

ओबीसी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी. उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल संगठन को मजबूत करना नहीं, बल्कि 2024 में खिसके सामाजिक आधार को दोबारा पार्टी के साथ जोड़ना भी है. बीजेपी लगातार चार बड़े चुनाव 2014 और 2019 के लोकसभा तथा 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव जीत चुकी है.

कांग्रेस की राजनीति का नया बैच

रायपुर. छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों प्रशिक्षण शिविर में संगठन को प्रशिक्षित कर रही है, लेकिन एक तस्वीर ने नेताओं से ज्यादा सीटों की राजनीति को चर्चा में ला दिया है. गाड़ी वही है, चेहरे भी वही हैं, लेकिन सीटों का गणित बदल गया है.

जिस सीट पर कभी भूपेश बघेल बैठते थे, वहां अब दीपक बैज नजर आ रहे हैं और जिस स्टीयरिंग पर कभी बाबा टीएस सिंहदेव की मौजूदगी चर्चा बटोरती थी, वहां अब भूपेश बघेल कमान संभाले दिखाई दे रहे हैं. अब इसे संयोग कहिए, संदेश कहिए या फिर कांग्रेस की नई राजनीतिक बैच की पहली क्लास. इस तस्वीर ने सियासी गलियारों में चर्चा जरूर छेड़ दी है.

गाड़ी वही, लेकिन सीटों का सिलेबस बदल गया- 21 जून को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए, संगठन को नया मंत्र दिया और 2028 की तैयारी का रोडमैप भी समझाया. इसके बाद कांग्रेस की गाड़ी फिर सड़क पर निकली, लेकिन इस बार चर्चा यात्रा की नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट की होने लगी. तस्वीर में गाड़ी वही दिखी, लेकिन सीटों का सिलेबस बदल चुका था. पुराने अध्याय की जगह नए किरदार दिखाई देने लगे.

कांग्रेस सरकार के दौर में जब भी बड़े राजनीतिक दौरे होते थे, गाड़ी में एक दृश्य अक्सर दिखाई देता था. स्टीयरिंग पर बाबा टीएस सिंहदेव और बगल वाली सीट पर भूपेश बघेल. लेकिन अब तस्वीर उलट गई है. स्टीयरिंग पर भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ बैठने की व्यवस्था है या फिर संगठन के भीतर बदलती भूमिका का संकेत भी?

क्या नई पीढ़ी की एंट्री?

तस्वीर का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है. जिस सीट पर कभी भूपेश बघेल बैठा करते थे, वहां अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस में संगठन और नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे लाने की चर्चा पहले से चल रही है. ऐसे में बैज का इस सीट पर नजर आना कई राजनीतिक अर्थ निकालने वालों को नया मसाला दे रहा है. राजनीति में कुर्सी, सीट और स्टीयरिंग सिर्फ सामान नहीं होते, इनके अपने प्रतीक होते हैं. कौन आगे बैठा है, कौन पीछे है, किसके हाथ में स्टीयरिंग है और किसे साथ बैठाया गया है, इन सबकी अपनी राजनीतिक व्याख्या होती है.

विशेष दूसरी बार विभाजन हुआ है और शरद पवार की पार्टी भी एक बार टूट चुकी है.

चुनाव नहीं जीत पा रहा है एमवीए

मुंबई. महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी यानी एमवीए की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेताओं के बयान सुनें तो ऐसा लगता है कि एमवीए की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाजपा उनकी पार्टियों को तोड़ रही है और कमजोर कर रही है. उद्धव ठाकरे की पार्टी में चार साल में दूसरी बार विभाजन हुआ है और शरद पवार की पार्टी भी एक बार टूट चुकी है. अब फिर से पार्टी टूटेगी या दोनों पार्टियां जुड़ेंगी यह देखने वाली बात होगी.

तभी विपक्षी पार्टियों के नेता यह रग आलापते हैं कि उनके नेता गद्दार हो गए या भाजपा ने भय और लालच से उनके नेताओं को तोड़ दिया. पर असली समस्या यह नहीं है.

असली समस्या यह है कि एमवीए की पार्टियां चुनाव नहीं जीत पा रही हैं. उनको जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है. एक के बाद एक चुनाव हारते जाने के कारण पार्टी और उसके नेतृत्व के प्रति नेताओं का भरोसा घट रहा है. महाराष्ट्र जैसे राज्य में ज्यादातर नेताओं के लिए सत्ता ऑक्सीजन की तरह है. उसके बगैर ज्यादा समय तक उनका काम नहीं चल सकता है. एमवीए के हारते जाने की ताजा मिसाल विधान परिषद की 17 सीटों के लिए हुआ चुनाव है. विधान परिषद के लिए स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाने वाली 17 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से 16 सीटें एनडीए ने जीतीं. इनमें से 11 सीटें भाजपा के खाते में गईं. शिव सेना ने तीन और एनसीपी ने दो सीट जीती. नासिक की एक सीट जो एनडीए नहीं जीत पाई वहां भी भाजपा के बागी गोकुल गीते ने शिव सेना के उम्मीदवार को हराया. इससे पहले इसी साल बृहन्नमुंबई महानगर निगम यानी बीएमसी सहित डेढ़ दर्जन शहरी निकायों में चुनाव हुए थे.